

THE
PARLIAMENTARY DEBATES
OFFICIAL REPORT

IN THE THIRD SESSION OF THE COUNCIL OF STATES
commencing on the 11th February 1953

COUNCIL OF STATES

Wednesday, 11th February 1953

The Council met at, four of the clock in the afternoon, MR. CHAIRMAN in the Chair.

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together today.

THE PRESIDENT (DR. RAJENDHA PRASAD):

राष्ट्रपति (डा० राजेन्द्र प्रसाद) : संसद् के सदस्यों, नौ महीने हुए जब हमारे संविधान के अनुकूल निर्वाचित प्रथम भारतगणराज्य संसद् के सदस्यों के रूप में आपका मैंने स्वागत किया था। तब से आपको बड़े भार वहन करने पड़े हैं और घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज जब यहां हम समवेत् हो रहे हैं हमें अपने देश के भाग्य में पूरा विश्वास है तथा यह आश्वासन है कि अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप हमारे लोग उस ध्येय की ओर बढ़ रहे हैं जिसे कि हमने अपने सामने रखा है। इन नौ महीनों में औद्योगिक और कृषिक दोनों ही प्रकार के अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है और उस पंचवर्षीय योजना को हमने अन्तिम रूप दे दिया है जिसने कि आगामी वर्षों में हमारी प्रगति की दिशा का चित्रण कर दिया है। अब हमारा यह काम है कि उस पथ पर हम बढ़े चले और जो प्रतिज्ञा अपनी जनता से की है उसको कार्यान्वित और पूरा करें। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पुरानी और नयी अनेक समस्याओं की भीड़ हम पर

तीसरी आवाज के त्रिने प्रस्तुत रहती है और हमारे सामर्थ्य और साधनों की अपेक्षा हमारी इच्छायें बहुधा ज्यादा तेज दौड़ लगाती हैं

२. इस समय जब कि हमें अपने नेताओं के सारे अनुभव और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है यह दुर्भाग्य की बात है कि अपने ज्येष्ठ राजनायकों में से अत्यन्त प्रमुख और लगन वाले एक राजनायक को हमने खो दिया है। बड़े दुःख के साथ मैंने यह सुना कि बड़े सवेरें कल श्री एन० गोपालस्वामी आर्यंगर की मृत्यु हो गई। अपने भरे पूरे जीवन में उन्होंने अनेक उच्च पदों को दुर्लभ योग्यता से सुशोभित किया था। अपना स्वास्थ्य तथा अपना आराम जिसके कि वह पूरी तरह मुस्तहक हो चुके थे उसका विचार न करके अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक वे अपने देश और जनता की सेवा में अपने जीवन को लगाये रहे। जब कोई भी कठिन समस्या हमारे सामने आती थी तो सरकार में उनके सहकारी और मैं उनकी परिपक्व बुद्धिमत्ता पर निर्भर करते थे। उनकी मृत्यु देश और हम सबके लिये भारी हानि है।

३. जब कि हम अपने देश में नवीन और समृद्ध भारत का निर्माण करने में तथा दरिद्रता के अभिशाप से जिन लाखों लोगों को गतकाल में इतना ज्यादा पीड़ित रहना पड़ा है उनको सुखसुविधा पहुंचाने के लिये लगे हुए हैं अवशिष्ट संसार की समस्याओं बलात् हमारे सामने आ खड़ी होती हैं और हम न तो उन से बच सकते हैं और न उनसे अपने को अलहदा रख सकते हैं। अन्य

[The President.]

देशों की बातों में हस्तक्षेप करने की मेरी सरकार की लेशमात्र भी इच्छा नहीं है किन्तु स्वतन्त्रता के साथ-साथ अनिवार्य रूपेण भारत पर जो जिम्मेदारी आ पड़ी है उसको तो इसे निभाना ही है। जैसा कि सर्व-विदित है हमने संसार के सब देशों के प्रति मैत्री और शान्ति की नीति बरतने का प्रयास किया है। शनैः शनैः वे लोग भी जो इसमें सर्वदा सहमत नहीं होते हैं, इसे समझने और इसका आदर करने लगे हैं, और यह बात मानी जाने लगी है कि भारत राष्ट्रों में शान्ति का हामी है और ऐसा कोई कदम उठाने से बचता रहेगा जिसका परिणाम लड़ाई की प्रवृत्ति को जगाना हो। इसी नीति के अनुसरणार्थ मेरी सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्ताव पेश किये थे जिनसे उसे यह आशा थी कि कोरिया युद्ध के बारे में समझौता हो जायेगा। इन प्रस्तावों को बहुत भारी समर्थन मिला, किन्तु दुर्भाग्यवश उन महान् देशों में से कुछ इन्हें स्वीकार न कर सके जिनका उससे निकटतम सम्बन्ध था। वह युद्ध जारी है, और उससे कोरिया की जनता को गहरी यातना और उसकी पूरी बरवादी ही नहीं हो रही है वरन् अवशिष्ट संसार के लिये वह खतरे का निशान भी है। दूर पूर्व पर असर डालने वाले हाल में किये गये कुछ दवतव्यों से और कोरिया में युद्ध का विस्तार करने वाले उनके जो परिणाम हो सकते हैं उनसे समस्त संसार भर में लोगों के मन में बहुत आशका पैदा हुई है। मेरी सरकार भी इन बातों को गम्भीर चिन्ता से देखती है। मुझे विश्वास है कि युद्ध जो अपने साथ पहले ही भारी विपत्ति लाया है उसके विस्तार की कोई भी प्रवृत्ति रोक ली जायेगी तथा राष्ट्रों और जातियों के मन को इन समस्याओं को शान्तिपूर्ण रीति से सुलझाने की ओर मोड़ दिया जायेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये मेरी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और किसी एक राष्ट्रपुंज के विरुद्ध

दूसरे राष्ट्रपुंज से गठबन्धन किये बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी। अपने देश में जिन लोकतन्त्रात्मक तरीकों से हम आवद्ध हैं उनमें समस्याओं को सुलझाने का शान्तिपूर्ण तरीका निहित है। यदि लोकतन्त्र को बचा रहना है तो वही शान्ति का वातावरण और समझौते की प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपना आवश्यक है।

४. निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा की बैठक फिर होगी और उन गम्भीर समस्याओं पर विचार करेगी जिन पर संसार में शान्ति अथवा युद्ध इस महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय ठहरा हुआ है। मेरी यह हार्दिक आशा है कि वे महान् राष्ट्र, जिनके प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठे होंगे, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में समाविष्ट उद्देश्यों के पूर्ण करने तथा समझौते की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिये प्रयास करेंगे।

५. अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेशवाद का आज भी सब से बड़ा क्षेत्र बना हुआ है हालत पहले से खराब हो रही है। मूलवशीय प्रभुता के सिद्धान्त का दक्षिण अफ्रीका में खुले आम ढिंडोरा पीटा जा रहा है और राज्य की पूरी शक्ति से उसे लोगों पर लादा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस समस्या को तय करने के जो प्रयत्न किये हैं दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनकी अवहेलना कर रही है। मूलवशीय विभेद के विरुद्ध आन्दोलन को, जो अपने शान्ति और अनुशासन पूर्ण ढंग के लिये उल्लेखनीय है, ऐसे कानून और सरकारी कार्यवाही द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है जो लोकतन्त्रात्मक तरीकों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उद्घोषित प्रयोजना की अवहेलना के लिये अभूत-पूर्व है। पूर्वी अफ्रीका में आज ऐसा मूलवशीय संघर्ष वर्तमान है जिसे यदि इस प्रकार खत्म न किया गया जिससे जनता को सन्तोष हो तो वह फल जायेगा और अफ्रीका के बहुत

व्यापक क्षेत्रों को आप्लावित कर लेगा। ऐसे अनेक लोग अब भी हैं जो इस बात को नहीं पहचानते कि आज की दुनिया में मूलवंशीय प्रभुता और विभेद को सहन नहीं किया जा सकता और इनको बनाये रखने के किसी भी प्रयास का परिणाम भयानक विपत्ति ही होगी।

६. पश्चिमी और दक्षिणपूर्वी एशिया के हमारे पड़ोसी देशों से हमारे सम्बन्ध घनिष्ट और मंत्रीपूर्ण हैं और हममें आपस में सहयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से भी जिज्ञासे से कि दुर्भाग्यवश हमारे सम्बन्ध खिंचे रहे हैं हमारे सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है। यह सुधार कुछ बड़ा नहीं है किन्तु यह ऐसा चिन्ह है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में हाल में हुए सम्मेलन मंत्रीपूर्ण वातावरण में हुए हैं और मुझे आशा है कि फलदायी सिद्ध होंगे। पारपत्र प्रणाली के शुरु किये जाने से दोनों देशों में जो उथल पुथल हुई थी वह शान्त हो गई है और इस प्रणाली के कारण जो बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हुई थीं वह अब शान्त दूर की जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रयत्न जारी रहेगा और ऐसे चलाया जायेगा कि पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों के सामने जो आधारभूत समस्याएँ अब भी हैं वे दूर की जा सकें।

७. अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की सहायता से दोनों देशों के प्रतिनिधि नहरों के पानी के प्रश्न पर शिल्पिक स्तर पर संयुक्त विचार कर रहे हैं। यह प्रश्न खासतौर पर ऐसा है कि जिस पर केवल वस्तुस्थिति की दृष्टि से ही तथा शान्तिपूर्ण विचार होना चाहिये जिससे कि दोनों देशों में होकर बहने वाले जल से दोनों देशों को महत्तम लाभ हो। इस जल का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ में ही समुद्र में चला जाता है। यदि इसको ठीक तरह से बांध लिया जाय तो भारत और पाकिस्तान दोनों के ही असंख्य लोगों को यह सुख मुविधाप्रद और समृद्धिकारी सिद्ध होगा। यह दुर्भाग्य

की बात है कि ऐसे प्रश्न पर भी वैमनस्य और होड़ की वृत्ति से और ऐसे वातावरण में विचार किया जाये। मुझे भरोसा है कि हमारा नया ढंग दोनों देशों के लिये फलदायी और सुन्दर परिणाम वाला होगा। यही ढंग निष्क्रान्त सम्पत्ति की उस समस्या को सुलझाने के लिये काम में लाया जा सकता है जिस समस्या से भारत और पाकिस्तान के लाखों लोगों की किस्मत बंधी हुई है।

८. भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरी सजीव समस्या जम्मू और कश्मीर राज्य की समस्या है। संयुक्तराष्ट्र के प्रतिनिधि के साथ हमारे प्रतिनिधि इस समस्या पर फिर बातचीत कर रहे हैं। अन्य समस्याओं के समान ही इस समस्या पर भी शान्त भाव से उस राज्य के लोगों के कल्याण को सर्वदा दृष्टि में रखकर विचार किया जाना चाहिये। लड़ाई या लड़ाई की धमकियों से यह अथवा भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य कोई अवशिष्ट समस्या हल नहीं की जा सकती। मेरा सरकार ने बार बार इस बात की घोषणा की है कि जब तक उस पर हमला न होगा वह युद्ध न छेड़ेगी और पाकिस्तान को भी इसने इसी प्रकार की घोषणा करने की दावत दी है। यदि लड़ाई का भय खत्म कर दिया जाये तो हमारे सामने जो सब समस्याएँ हैं उन पर विचार करना कहीं अधिक आसान होगा।

९. अन्दरूनी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत प्रकार से तरक्की हुई है। उस राज्य से भारत के सम्बन्ध के बारे में हमारे संविधान में विशिष्ट उपबन्ध हैं और भारत सरकार तथा जम्मू और कश्मीर के बीच हुए समझौते द्वारा उन बन्धनों को जो उस राज्य को भारत से बांधे हुए हैं और भी सुदृढ़ और घनिष्ट कर दिया गया है। इस समझौते के एक भाग पर अमल हो चुका है और अवशिष्ट भाग जल्द ही अमल में लाया जायेगा।

[The President.]

दुर्भाग्यवश जम्मू में नासमझी से एक आन्दोलन शुरू किया गया है; यद्यपि उसका उद्देश्य भारत से और अधिक निकट एकता कायम करना है तथापि यह सम्भावना है कि उसका परिणाम बिल्कुल उलटा ही हो। मुझे आशा है कि यह पथ भ्रष्ट आन्दोलन शीघ्र ही बन्द हो जायेगा और जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के विशाल संघ में उस राज्य की प्रगति और अभिवृद्धि के लिये सहयोग करेंगे। जहां भी कोई न्यायपूर्ण शिकायतें होंगी उनकी निःसन्देह जांच की जायेगी और उन्हें दूर करने की हर कोशिश की जायेगी।

१०. भाषावार प्रान्तों के प्रश्न के कारण देश के विभिन्न भागों के लोग बहुधा आन्दोलित हुए हैं। जहां कि राज्य निर्माण में भाषा और संस्कृति महत्वपूर्ण बातें होती हैं वहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि राज्य भारत संघ में प्रशासनीय इकाइयां हैं और उनके बारे में अन्य बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सर्वोपरि यह बात है कि भारत की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वदा प्रथम पूर्ववर्तिता देनी आवश्यक है। वैयक्तिक और प्रशासनिक बातों और साथ साथ ही आर्थिक प्रगति का भी इस सम्बन्ध में महत्व है। इन सब तत्वों को दृष्टि में रखने पर ऐसा कोई कारण नहीं रहता कि राज्यों के पुनर्संगठन के प्रश्न पर पूरी तरह से और शान्त भाव से इस प्रकार विचार न किया जाये जिससे कि जनता की इच्छाएं भी पूर्ण हों और उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में सहायता मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पृथक आन्ध्र राज्य के निर्माण के विषय में मेरी सरकार ने कदम उठाये हैं, और मुझे आशा है कि इस नये राज्य की स्थापना में अधिक विलम्ब न होगा। नये राज्य की स्थापना के सम्बन्ध

में ऐसे किसी परिवर्तन के लिये तत्सम्बन्धित सब लोगों के पूरे पूरे सहयोग की आवश्यकता होती है, और मुझे आशा है कि यह सहयोग प्राप्य भी होगा।

११. योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे कर अपने काम का पहला भाग समाप्त कर लिया है। दूसरा और अपेक्षाकृत अधिक मुश्किल भाग अर्थात् योजना को कार्यान्वित करने का काम देश के सामने है और उसमें हमें अब लग जाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह योजना तथा देश में जो पचपन (५५) सामुदायिक योजनाएं (कम्युनिटी प्रोजेक्ट) शुरू की गयी हैं वे हमारी जनता में भारी उत्साह पैदा कर रही हैं। कुछ ही महीनों में सैकड़ों मील लम्बी सड़कें बना ली गई हैं, तालाब खोद लिये गये हैं, पाठशाला गृह निर्मित कर लिये गये हैं, और अन्य बहुत से छोटे मोटे काम हाथ में लिये गये हैं जो कि लगभग सारे ही हमारी जनता ने स्वेच्छा श्रम से पूरे किये हैं। यह आशा और आश्वासन का चिन्ह है क्योंकि अन्ततोगत्वा हमारी जनता पर ही यह निर्भर करता है कि वह अपना भविष्य कैसा बनाये।

१२. देश की साधारण आर्थिक अवस्था में भी सुधार के स्पष्ट चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि अब भी दुर्भाग्य से ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां सूखा के कारण दुर्भिक्षसम स्थिति वर्तमान है। उपयोगी कामों द्वारा अथवा अन्य रीति से लोगों को सहायता देने के लिये इन क्षेत्रों में राज्य सरकारें पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। किन्तु इस समस्या का तो अपेक्षाकृत अधिक मौलिक तरीके से हल करना आवश्यक है जिससे कि दुर्भिक्ष की स्थिति की पुनरावृत्ति से तथा और अनिश्चयजन्य वर्षा पर पूर्णतया आश्रित रहने से बचा जा सके।

१३. संविधान के अनुच्छेद २८० के उपबंधों के अधीन १९५१ के अन्तिम दिनों में संगठित वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है। आयोग की सिफारिशों को मेरी सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। चालू सत्र में आयोग की सिफारिशें संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रख दी जायेंगी।

१४. खाद्य स्थिति में निरन्तर सुधार होता रहा है और १९५२ के अन्त में १९ लाख टन का भण्डार हमारे पास था जिसका परिमाण उससे पहले कभी के प्रे कहीं अधिक है। जिन साधनों से यह भण्डार इतना बन सका उनमें से एक साधन अमरीका के संयुक्त राज्य से उधार मिला गेहूँ है। १९५२-५३ के वर्ष के लिये खाद्यान्नों की प्राप्यता की संभावना पिछले दो वर्षों से कहीं अधिक अच्छी है। अपर्याप्त वर्षा के कारण मुम्बई, मद्रास और मैसूर के भागों में सूखा पड़ने से खाद्यान्नों का आयात करना होगा किन्तु पिछले वर्षों से उसका परिमाण कम होगा। यह अत्यन्त महत्व की बात है कि हम खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बन जायें और मुझे आशा है कि पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट तीन वर्षों के अन्दर यह बात सम्भवतः ही जायेगी। यह पहली बार है कि हम खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डार सहित वर्ष का प्रारम्भ कर रहे हैं। हमें इसको इतना बड़ा बनाने का प्रयास करना चाहिये जिससे कि हम किसी अनसोची स्थिति का सामना कर सकें। हाल के महीनों में खाद्यान्नों की कीमतों का झुकाव नीचे की ओर रहा है। भारत के बहुत से भागों में नियन्त्रणों को ढीला कर दिया गया है और अन्न को लाने ले जाने की अधिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई है। किन्तु सरकार का यह विचार है कि खास मुकामों पर नियन्त्रण को बनाये रखे जिससे कि ऐसा कोई अदृश्य

परिणाम न हो जिनका कि कीमतों का अनाज की बसुली पर बुरा प्रभाव पड़े।

१५. १९५१-५२ में शक्कर की पैदावार १५ लाख टन हुई जितनी की पहले कभी नहीं हुई थी। यह पहला ही मौका था जब हमारी अन्दरूनी जरूरतों के मुकाबले में पैदावार ज्यादा हुई। इसके फलस्वरूप यह सम्भव हुआ कि १९५२-५३ के मौसम में पैदा की जाने वाली शक्कर तथा गुड़ और खंडसारी की कीमतों, यातायात और वितरण पर नियन्त्रण ढीला किया जा सके। मुंगफली के तेल के पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप उन नियन्त्रणों के सिवाय जो उसकी अच्छी किस्म को बनाये रखने के लिये जरूरी हैं, हमने उद्वेगित तेलों की कीमतों पर से अन्य नियन्त्रण हटा लिये हैं।

१६. रूई और पटसन की पैदावार में भी बहुत भारी प्रगति हुई है। १९४८-४९ में रूई की पैदावार १७.७ लाख गांठ और पटसन की २०.७ लाख गांठ थी। १९५१-५२ में यह बढ़ कर रूई की पैदावार ३१.३ लाख गांठ और पटसन की ४६.८ लाख गांठ हो गई।

१७. देश के खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने के लिये दो हजार ट्यूबवेल बनाने के लिये तथा छोटे मोटे सिंचाई के कामों के कार्यक्रम को तेजी से पूरा करने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फसल प्रतियोगितायें अधिकाधिक मात्रा में सारे देश में जनप्रिय होती जा रही हैं, और इनसे बड़े उल्लेखनीय परिणाम हुए हैं। धान की खेती के लिये उस रीति को जो जापानी रीति कही जाती है आरम्भ करने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयोग किये जा रहे हैं। इस रीति से यह आशा की जाती है कि पैदावार बढ़ाने में इसके बहुत ठोस परिणाम होंगे। जम्मू प्रान्त में एक विस्तृत यन्त्र सज्जित फार्म शुरू किया गया है। उर्वरकों और अन्य प्रकार के खाद के विस्तृत प्रयोग तथा अच्छी किस्म के बीज के प्रयोग

[The President.]

के लिये जोरों से प्रयास किये जा रहे हैं। खास तौर पर सामुदायिक केन्द्र इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि विभिन्न तरीकों से जिन में ग्राम्य विस्तार सेवा भी सम्मिलित है खाद्यान्नों की पैदावार को बढ़ाया जाये।

१८. ढोरों के सुधार के लिये ९२ प्रमुख फार्म केन्द्र १९५१-५२ में शुरू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त यह विचार है कि प्रत्येक सामुदायिक योजना क्षेत्र में एक प्रमुख ग्राम्य इकाई कायम की जाय। अच्छी किस्म की ऊन की पैदावार के लिये प्रबन्ध करने के हेतु भेड़ अभिजनन की योजना का पुनर्संगठन किया गया है। वन्य जीवन के बनाये रखने के लिये एक मंडल की स्थापना की गई है। जोधपुर में मरुभूमि-वनरोपण गवेषणालय संस्थान की स्थापना की गई है। मरु क्षेत्रों के सुधार का काम यह अपने हाथ में लेगा।

१९. १९५२ में सिन्दरी उर्वरक कारखाने ने एक लाख अस्सी हजार टन एमोनियम सल्फेट बनाया है। १९५३ में इसकी संख्या बढ़कर ३ लाख टन हो जायेगी, ऐसी आशा है। इसकी दर ३६५ रुपया प्रति टन से घटाकर ३३५ रूपया प्रति टन कर दी गई है।

२०. १९५२ में सूती कपड़े की पैदावार जो कि ४ अरब साठ करोड़ गज थी बहुत ही सन्तोषप्रद रही और अगले वर्ष के लिये और भी अधिक पैदावार की सम्भावना है। यद्यपि मिल निर्मित कपड़े की कीमतों का कम होना खुशी की बात है तथापि उसके कारण करघे के बने कपड़े की बिक्री कम हो गई। और करघा वस्त्र व्यवसाय को विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है; इस व्यवसाय से हमारे देश में लाखों आदमियों की जीविका चलती है। मेरी सरकार इसको और अन्य कटीर उद्योगों को बहुत महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि यह बहुत लोगों को रोजगार प्रदान

करते हैं और इसलिये भी क्योंकि बेकारी को दूर करने के ये अत्यन्त प्रभावी साधन हैं। अखिल भारतीय खादी और ग्राम्य उद्योग मण्डल की स्थापना की गई है और ग्राम्य तथा कूटीर उद्योगों के लिये आवश्यक शिल्पिक विकास और गवेषणा के लिये धन प्राप्त करने के लिये कानून बनाया जा रहा है। करघा वस्त्र व्यवसाय को सहायता देने के लिये मिल उद्योग द्वारा बनाई जाने वाली धोतियों का परिमाण १९५१-५२ की पैदावार का साठ प्रतिशत कर दिया गया है।

२१. अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के गिरने के कारण चाय व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। चाय बागान को अपेक्षाकृत अच्छी साख सुविधायें दिलाने के लिये सरकार ने कार्रवाई की है और उसका इरादा है कि चाय उद्योग के हर पहलू की जिस में बाजार में माल भेजने की व्यवस्था भी सम्मिलित होगी जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये। चाय की कीमतों में सुधार के चिन्ह अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

२२. संसार व्यापी कीमतों में पुनर्संयोजन से वैदेशिक व्यापार और निर्यात कीमत में कम हुआ है, और कुछ कम सीमा तक उसकी मात्रा में भी कमी हुई है। भुगतान संतुलन की स्थिति भी संतोषजनक रही है क्योंकि आयात भी कम हुआ है।

२३. भारत के उत्तर पूर्व और अन्य जन जाति क्षेत्रों के प्रति मेरी सरकार विशेष ध्यान देती रही है और उनके विकास के लिये सहायता दी जा रही है। पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की गई है। भारत में समाचार पत्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति की गई है।

२४. बड़ी बहुमुखी नदी योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है और उनमें से कुछ प्रवर्तन स्थिति में जल्द ही आने वाली है। अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य में निरन्तर प्रगति हो रही है।

२५. विशाखापट्टनम् में हिन्दोस्तान नौप्राण की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिये तथा लोहे और इस्पात उद्योग के विस्तार के लिये कदम उठाये गये हैं। कोयला, इस्पात, सीमेन्ट, नमक और उर्वरकों की पैदावार पिछले वर्ष से उच्चतर स्तरों पर पहुँच गई है।

२६. नये राष्ट्रीय प्रयोगालयों और गवेषणा प्रतिष्ठानों की स्थापना द्वारा वैज्ञानिक गवेषणा में और अधिक प्रगति हुई है। केन्द्रीय विद्युत रसायनिक गवेषणा प्रतिष्ठान कराईकूड़ी में खोला गया है, और मद्रास में केन्द्रीय चर्म गवेषणा प्रतिष्ठान खोला गया है। शीघ्र ही रुड़की में वास्तु गवेषणा प्रतिष्ठान खोला जाएगा मोनाजाईट बालुका विधायन के लिये तिरुवांकुर—कोचीन में अलवाई में कारखाना स्थापित किया गया है और मुम्बई राज्य में अम्बरनाथ में यन्त्रीकरण आद्यरूप कारखाने को हाल में खोला गया है। बंगलौर के हिन्दोस्तान विमान कारखाने ने अपनी ही प्ररचनाओं के अनुकूल कई प्रशिक्षक विमान बनाये हैं जो अब काम में आ रहे हैं। जबलपुर के निकट एक प्रतिरक्षा कारखाना बन कर पूरा होने वाला है।

२७. मेरी सरकार ने यह निश्चय किया है कि वर्तमान वैमानिक समवायों को अपने नियन्त्रण में ले ले और अनुसूचित वैमानिक चर्याओं को चलाये। इस प्रयोजन के लिये दो राज्य निगम स्थापित करने का विचार है। एक आन्तरिक चर्याओं के लिये और दूसरा बाह्य चर्याओं के लिये।

२८. भारतीय रेलें अगले मास में अपनी शताब्दि प्रदर्शनी का समारोह कर रही हैं।

यह राज्य उपक्रम जिस पर समुदाय का आधिपत्य है प्रगति करता रहा है और अपने कार्यक्षेत्र को बड़ा रहा है।

२९. किसी जाति या राष्ट्र की प्रगति अन्ततोगत्वा शिक्षा पर निर्भर करती है। देश में शिक्षा की वर्तमान अवस्था के बारे में मेरी सरकार को बहुत चिन्ता है। इसमें गुण और परिमाण दोनों ही से सम्बन्धित अनेक प्रकार की कमियाँ हैं और डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने की ओर इसमें बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शिल्पिक विषयों में और सर्वोपरि अच्छी नागरिकता के लिये प्रशिक्षा में व्यक्तित्व के वास्तविक सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। बुनियादी तालीम एक प्रतिमान के रूप में शुरू की गई है किन्तु इस दिशा में दुर्भाग्यवश अब तक प्रगति बहुत धीमी हुई है। बुनियादी, माध्यमिक और सामाजिक शिक्षा के सुधार की बहुत सी योजनाएँ विचाराधीन हैं और माध्यमिक शिक्षा के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया है।

३०. भारत की स्थिति पर सब ओर से दृष्टि डालने से यह प्रतीत होता है कि बढ़ती हुई गति से चतुर्मुखी प्रगति हुई है। यह सन्तोष की बात है। किन्तु जो ध्येय हमने अपने सामने रखा है वह अभी बड़ी दूर है। और उसके लिये अधिक और लगातार प्रयास की तथा अधिक गतिशील परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य ऐसा कल्याणमय राज्य है जिसमें इस देश के सब लोग भागीदार होंगे, और इसके लाभों और आभारों में समान रूप से अंश बटायेंगे। जब तक दरिद्रता और बेकारी है समुदाय के एक विभाग को इस साझेदारी से कोई लाभ नहीं मिलता। अतः यह आवश्यक है कि हमारा यह ध्येय हो कि सब लोग पूरी तरह से और उत्पादक कार्य में लग जायें।

[The President.]

३१. १९५३-५४ के वैत्तिक वर्ष के लिये भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण आपके सामने रखा जायेगा। लोक सदन के सदस्यों से अपेक्षा की जायेगी कि वे अनुदान भांगों पर विचार करें और उन्हें स्वीकार करें।

३२. चालू वैत्तिक वर्ष में होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिये अनुपूरक अनुदानों को स्वीकार करने के लिये आप से कहा जायेगा।

३३. आपके सामने २४ विधेयक लम्बित हैं। कुछ ने तो समिति प्रक्रम पार कर लिया है। उनमें से कुछ जो अब भी समितियों के विचाराधीन हैं, इस सत्र के अन्तर्गत उनकी सिफारिशों सहित आपके सामने लाये जायेंगे।

३४. आपके सामने जो अन्य विधायक प्रस्ताव लाये जाने उद्दिष्ट हैं उनमें से कुछ का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। लोक-प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय गृह संयोजन विधेयक, वैमानिक चर्चा निगम विधेयक, न्यूनतम भूति (संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक।

३५. मुझे हार्दिक भरोसा है कि बुद्धिमत्ता और सहिष्णुता तथा सहयोगात्मक प्रयत्न की प्रवृत्ति आपका आपके काम में पथ प्रदर्शन करेगी और जिस देश और जनता की सेवा का सौभाग्य हम सब को प्राप्त है उनके लिये सुन्दर फल प्रदान करेगी।

THE PRESIDENT (DR. RAJENBRA PRASAD): Members of Parliament, nine months ago, I welcomed you as members of the first Parliament of the Republic of India, elected under our Constitution. Since then, you have had to shoulder heavy burdens and to face difficult problems, both domestic and international. As we meet here today, we bring with us faith in our country's destiny and the assurance that our people are advancing, through

their labours, towards the goal that we have set before us. These nine months have seen advances on many fronts, industrial and agricultural, and the finalisation of the Five Year Plan, which has mapped out the lines of our progress in the coming years. It is for us now to march along that path and to implement and fulfil the promise held out to our people. That is no easy task, for a multitude of old and new problems always tend to overwhelm us and our wishes often run faster than our capacity and resources.

2. At this moment, when we require all the wisdom and experience of our leaders, it is a misfortune that we have lost one of the most eminent and devoted of our elder statesmen. I learnt with deep sorrow of the death yesterday, in the early morning, of Shri N. Gopalaswami Ayyangar, who had filled, in the course of a full life, many high offices with rare distinction. To the end of his days, regardless of his health and the leisure he had so richly earned, he devoted his life to the service of his country and people. His colleagues in the Government and I relied on his ripe wisdom whenever any difficult problem confronted us. His death is a great loss to the country and to all of us.

3. While we labour in our own country to build up a new and prosperous India, bringing relief to the millions who have suffered so much in the past - from the curse of poverty, the problems of the rest of the world thrust themselves upon us and we cannot avoid them or isolate ourselves from them. My Government has no desire to interfere with other countries, but it has to face the responsibility which has inevitably come with independence to India. We have endeavoured, as is well known, to pursue a policy of peace and of friendship with all the countries of the world. Gradually, that policy has been understood and appreciated, even by those who may not always agree with it, and it is recognised that India stands for peace among the nations and will avoid taking any step which might encourage the tendency to war. In pursuit

of this policy, my Government put forward certain proposals which they hoped might lead to a settlement of the Korean war. Those proposals met with a very large measure of support, but unfortunately some of the great countries most intimately concerned were unable to accept them. This war continues not only to the utter misery and ruin of the people of Korea, but also as a focus of danger for the rest of the world. Certain statements recently made, and the consequences that might flow from them in extending the war in Korea, have caused considerable apprehension in the minds of people all over the world. My Government has viewed these developments with grave concern. I trust that any tendency towards an extension of the war which has already brought disaster in its train, will be checked and the minds of nations and peoples will be turned towards a peaceful approach to these problems. My Government will continue to work to this end and will pursue a policy of friendship with all countries without any alignment with one group of nations against another. The democratic processes to which we are so firmly committed in our own country involve methods of peaceful approach to problems. If democracy is to survive, the same climate of peace and spirit of reconciliation has to be extended to the international sphere.

4. The General Assembly of the United Nations will meet again in the near future and will consider these grave problems, on which hangs the momentous issue of peace or war in the world. I earnestly hope that the great nations whose representatives will assemble there will address themselves to the promotion of a spirit of reconciliation- and the fulfilment of the objectives embodied in the Charter of the United Nations.

5. In the continent of Africa, which continues to be the greatest sphere of colonialism today, events have taken a turn for the worse. In South Africa, the doctrine of racial domination is openly proclaimed and enforced by all the power of the State. The efforts

62 C of S.

made by the United Nations to deal with this problem have been ignored by the Government of the Union of South Africa. A movement against racial discrimination, which was remarkable for its peaceful and disciplined character, is sought to be crushed by legislation and governmental action, which are unique in their denial of democratic processes and the purpose which was proclaimed in the Charter of the United Nations. In East Africa there is racial conflict which, if not ended to the satisfaction of the people, is likely to extend and engulf vast areas of Africa. There are many people still who do not realise that racial domination and discrimination cannot be tolerated in the world today and any attempt to perpetuate them can only lead to disaster.

G. Our relations with our neighbour countries in Western and South-Eastern Asia continue to be close and friendly and there is an increasing measure of co-operation between us. Even in regard to Pakistan, with which unfortunately our relations have been strained, there has been a certain improvement. That improvement is not very great, but it is an indication which I welcome. Recent conferences between representatives of the two countries have been held in a friendly atmosphere and will, I hope, yield results. The upheaval caused by the introduction of the passport system between the two countries has subsided and many of the difficulties that were created by this system are being gradually removed. I trust that this effort will be continued and directed towards the removal of the basic problems that still confront the minorities in East Bengal.

7. The canal waters issue is being considered at a technical level jointly by representatives of the two countries, assisted by the International Bank. This issue is eminently one which ought to be considered objectively and dispassionately so that the maximum advantage can be derived by both countries from the waters that flow through them. A great proportion of these waters run waste to the sea. If they can be properly harnessed,

[The President.] they will bring relief and prosperity to vast numbers of human beings in both India and Pakistan. It is unfortunate that an issue like this should be treated in a spirit and atmosphere of rivalry and hostility. I trust that the new approach will yield fruitful and happy results to both countries. This approach can also be applied to the settlement of the evacuee property problem which affects the fortunes of millions of people both in India and Pakistan.

8. Another vital issue between India and Pakistan has been the Jammu and Kashmir State. This matter is again being discussed by our representatives with the Representative of the United Nations. That issue, like others, has to be considered dispassionately, keeping always the welfare of the people of that State in view. It is not by war or threats of war that this, or any other outstanding problem between India and Pakistan, can be solved. My Government has declared repeatedly that it will not go to war unless it is attacked, and has invited a like declaration by Pakistan. If fear of war was eliminated, it would be much easier to consider all the issues that confront us today.

9. Internally, in the Jammu and Kashmir State, progress has been made in many ways. Our Constitution contains specific provisions about the relationship of India with the State, and by an agreement between the Government of India and the Jammu and Kashmir Government, the bonds that tie that State to India have been strengthened and made closer. A part of this agreement has been implemented and the remaining part should also come into operation soon. Unfortunately a misconceived agitation was started in Jammu which, though aiming at a closer union with India, is likely to have exactly the opposite effect. I trust that this misguided agitation will cease and the people of Jammu and Kashmir will co-operate for the progress and advancement of the State in the larger Union of India. Where there are legitimate grievances, they will undoubtedly be enquired into and every effort made to remove them.

10. The question of linguistic provinces has often agitated the people in various parts of the country. While language and culture are important considerations in the formation of States, it has to be remembered that the States are administrative units in the Union of India and that other considerations also have to be kept in mind. Above all, the unity of India and national security have always to be given the first priority. Financial and administrative aspects, as well as economic progress, are also important. Keeping all these factors in view, there is no reason why the question of the reorganisation of States should not be considered fully and dispassionately so as to meet the wishes of the people and help in their economic and cultural progress. I am glad that my Government has taken steps in the matter of the formation of a separate Andhra State and I hope that there will be no great delay in establishing this new State. Any such change as the establishment of a new State demands the fullest co-operation of all those concerned with it and I trust that this will be forthcoming.

11. The Planning Commission has completed the first part of its labours by finalising its report on the Five Year Plan. The other and the more difficult part, of implementing this plan, now faces the country and to that we must address ourselves. I am glad to find that this Plan and the fifty-five Community Projects that have been started in the country are evoking a considerable degree of enthusiasm among our people. In the course of a few months, hundreds of miles of roads have been built, tanks dug, school houses constructed and many other minor projects undertaken, almost entirely by the voluntary labour of our people. That is a sign of hope and promise, for it lies with our people ultimately what they make of their future.

12. The general economic situation in the country shows distinct signs of improvement, although there are still unfortunately areas where, owing to lack of rain, near-famine conditions

prevail. The State Governments are doing their utmost to give relief by utility works or otherwise in these areas. The problem, however, has to be tackled in a more basic way so as to avoid recurrence of famine conditions and a complete dependence upon the vagaries of the monsoon.

13. The Finance Commission, constituted towards the end of 1951 under the provisions of Article 280 of the Constitution, have submitted their report. The Commission's recommendations have been accepted by my Government and necessary action will be taken for implementing them. The recommendations of the Commission will be laid on the Table of Both Houses of Parliament in the current session.

14. There has been a steady improvement in the food situation and the closing stock for 1952 was 19 lakh tons, which is the highest on record so far. One of the factors in building up this stock was the wheat loan from the U.S.A. The prospects of foodgrains for 1952-53 are better than in the two preceding years. Owing mainly to the drought in parts of Bombay, Madras and Mysore, caused by an inadequate monsoon, foodgrains will have to be imported, but their quantity will be less than in the last two years. It is of the highest importance that we should gain self-sufficiency in food and I hope that this might be possible within the three remaining years of the Five Year Plan. For the first time we start this year with a considerable stock of food-grains. We should endeavour to build this up so that we can meet any contingency. Prices of foodgrains have shown a downward trend in recent months. Controls have been relaxed in many parts of India and there is greater freedom of movement. The Government, however, intend to retain control at strategic points so that no untoward results may affect prices or procurement.

15. The production of sugar during 1951-52 reached the record figure of 15 lakh tons and for the first time pro-

duction exceeded internal requirements. This made it possible to relax control over the prices, movement and distribution of sugar, as well as on gur and khandsari. With the easing of the supply position of groundnut oil, controls of prices on hydrogenated oils have also been lifted, except those intended to ensure quality.

16. Very considerable progress has been made in cotton and jute production. In 1948-49 cotton production amounted to 17;7 lakh bales and jute 20;7 lakh bales. In 1951-52 cotton had increased to 31 • 3 lakh bales and jute to 46 ;8 lakh bales.

17. In order to add to the country's food production, special attention is being paid to the construction of more than 2,000 tube-wells and for an accelerated programme of minor irrigation works. Crop competitions are becoming increasingly popular all over the country and have yielded very remarkable results. Large-scale experiments are being made to introduce what is called the Japanese method of rice cultivation which promises substantial results in increase of yield. A large mechanised farm has been set up in Jammu Province. Vigorous attempts are being made for the extensive; application of fertilizers and other manure and for the use of improved seeds. The community centres are specially aiming at increasing the yield of foodgrains by various methods, including a rural extension service.

18. For the improvement of cattle 92 key farm centres were started in 1951-52. In addition it is proposed to provide one key village unit in each Community Project area. Sheep breeding schemes have been reorganised to provide for the production of fine wool. A Board for the preservation of wild life has been set up. At Jodhpur a Desert Afforestation Research Station is being established. This will undertake work for the reclamation of arid areas.

19. The Sindri Fertilizer Factory produced 180,000 tons of ammonium sulphate during 1952. This is expected

[The President.] to be increased to three lakh tons in 1953. The pool price has been reduced from R> 365 per ton to Rs. 335.

20. The production of cotton textiles, which amounted to 4,600 million yards during 1952, was highly satisfactory and the prospects for the next year are good. The lower prices of mill-made cloth, though welcome, led to a fall in the offtake of handloom cloth and the handloom industry, which provides livelihood to millions of people in the country, was faced with serious difficulties. My Government attaches great importance to this and other cottage industries both because vast numbers of people are employed in them and because they are the most effective method of removing unemployment. An All-India Khadi and Village Industries Board has been established and legislation undertaken to raise funds for technical development and research for village and cottage industries. In order to help the handloom industry, the production of dhoties by Tiill industry was curtailed to sixty per cent, of the 1951-52 production.

21. The tea industry was badly affected by the fall in international prices. The Government have taken measures to assist tea gardens to secure better credit facilities and propose to set up an expert committee to enquire into all aspects of the tea industry, including marketing. The price of tea is now showing some signs of improvement.

22. The readjustment of world prices affected foreign trade and exports fell in value and to a lesser extent, in quantity. The balance of payments position, however, continued to be satisfactory, as imports also declined.

2a. My Government has been paying special attention to the tribal areas in the North-East and other parts of India and help is being given for their development. A Commission to consider the problems of backward classes has been appointed. A Press Commission has also been appointed to consider problems of the newspaper press in India.

24. The great multi-purpose river valley projects have made good progress and in some of them the operational phase will begin soon. Work on other projects has made steady progress.

25. Steps are being taken to improve the efficiency of the Hindustan Shipyard at Visakhapatnam and for the

- expansion of the Iron and Steel Industry. Production of coal, steel, cement, salt and fertilizers has reached higher levels than in the previous year.

26. Scientific research has made further progress by the establishment of new National Laboratories and Research Institutes. A Central Electro-Chemical Research Institute was opened at Karaikudi and the Central Leather Research Institute at Madras. The Building Research Institute at Roorkee will be opened soon. A factory for processing monazite sands has been set up at Alwaye in Travancore-Cochin and a Machine Tool Prototype factory was recently opened at Ambernath in Bombay State. The Hindustan Aircraft Factory at Bangalore has produced, from its own designs, a number of trainer aircraft which are being used now. A defence factory near Jubbulpore is nearing completion

27. My Government has decided to take under State control the existing air companies and to operate the scheduled air services. It is proposed to establish two State Corporations for this purpose, one for internal services and the other for external services.

28. Indian Railways are celebrating their centenary next month. This great State undertaking belonging to the community is continuing its progress and extending its operations.

29. The progress of a people and of a nation ultimately depends upon education. My Government views with much concern the present state of education in the country which suffers in many ways, both in quality and quantity, and too much attention is paid to the granting of diplomas and degrees and not to the real improvement of the individual in cultural, scientific and technical

matters and, above all, in the training for good citizenship. Basic education has been adopted as the model, but progress in this has thus far been unfortunately slow. Many schemes for the improvement of basic, secondary and social education, are under consideration and a Commission on Secondary Education has been appointed.

30. An over-all view of the situation in India indicates allround general progress at an increasing pace. This is a matter for satisfaction. But the goal we have set before us is still far and requires greater and continuous effort and an increasing pace of change. We aim at a Welfare State in which all the people of this country are partners, sharing alike the benefits and the obligations. So long as there is poverty and unemployment, a section of the community derives no benefit from this partnership. It is, therefore, necessary for us to aim at full and productive employment.

31. A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1953-54 will be laid before you. The Members of the House of the People will be required to consider and pass the demands for grants.

32. The House of the People will also be asked to vote supplementary grants to meet additional expenditure during the current financial year.

33. There are 24 Bills pending before you. Some of them have passed the Committee stage. A few of them, which are still under consideration by the Committees, will be brought before you with their recommendations during the course of this session.

34. Among the other legislative measures that it is intended to bring before you, the following may be especially mentioned : The Representation of the People (Amendment) Bill, the Bill on National Housing, the Air Services Corporation Bill, the Minimum Wages (Amendment) Bill, and the Indian Tariff (Amendment) Bill.

35. I earnestly trust, that wisdom and tolerance and the spirit of cooperative endeavour will guide you in your labours and will yield results for the good of the country and the people whom we are all privileged to serve.

DEATH OF SHRI N. GOPALASWAMI AYYANGAR

THE PRIME MINISTER AND MINISTER FOR EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JAWAHARLAL NEHRU) : Mr. Chairman, before this House enters upon the labours of this session, may I refer to the passing away of a colleague of ours and the Leader of this House, Shri Gopaldaswami Ayyangar? During the last session he was unable to attend to the business of this House because of his illness, and we all thought that it was, if I might call it so, a temporary illness which would pass, because we could not reconcile ourselves to the thought that he would not come back. We had come to rely upon him in so many matters that, as often happens, he became, in his own way, a kind of institution in Government to whom all turned for advice whenever any difficulty arose. And so we took this institution for granted. When untoward events take place, they rather shake up the whole fabric of things. So it has been in this case, and though we grieve for him, in reality we grieve for ourselves, because he is not there for us to turn to. We may send our messages of sympathy to his family and others, and it is right that we should do so; but those who require most sympathy are ourselves.

Mr. Gopaldaswami Ayyangar had a background and a record which, I suppose, is unusual in this House or among members of Government. Starting in the junior scale of Government service, he rose step by step till he seemed to be peculiarly fitted for any difficult problem or post of responsibility that might arise. In the course of his long and varied career he was, as the House might know, Prime Minister of the State of Jammu and Kashmir for five or six years. Those years were difficult years. Those years were war